

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 648वीं बैठक दिनांक 30/05/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9931/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Bichhondana Sand Quarry in an area of 1.640 ha. (4950 cum per annum) (Khasra No. - 1282), Village- Bichhondana, Tehsil- Bhandar, District- Datia (M.P).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. - 1282), Village- Bichhondana, Tehsil- Bhandar, District- Datia (MP) 1.640 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 07 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान पहुज नदी में स्थित है प्रस्तावित खदान नदी धारा के बीच में स्थित है नदी का प्रवाह खदान क्षेत्र में से होकर निकल रहा है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र का वह भाग जो नदी के प्रवाह में वह भाग नॉन माईनिंग के रूप में छोड़ा जायेगा एवं वहां खनन कार्य प्रस्तावित नहीं है एवं नदी धारा को कास नहीं करेंगे एवं रेत का इवेक्यूशन दक्षिण-पश्चिम दिशा से किया जाना प्रस्तावित है। नदी के अपस्ट्रीम में एक निर्माणाधीन रोड़ ब्रिज 385 मीटर की दूरी पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ब्रिज के डाऊन स्ट्रीम में खदान स्थित है परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में से नदी का प्रवाह होने के कारण लगभग 0.4629 हे० क्षेत्र हुआ है जो कि नॉन माईनिंग एरिया

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

प्रस्तावित है तथा लगभग 0.9840 हे० क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। अतः वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार हो रही है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. —14 के सरल क्रमांक—16 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल—8474 घन मी. उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 4950 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। यदि वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव किया जावेगा एवं तत्संबंध में राशि ग्राम पंचायत को दी जायेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक—बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 4950 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 05.96 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.08 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण प्रथम वर्ग (दिनांक 30.6.2023 तक) में किया जावेगा। अथवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण योजना में होने वाले व्यय को संबंधित ग्राम पंचायत अथवा वन विभाग को निर्धारित राशी रु. 2,12,500 और 10 परसेंट रख रखाव के लिए 21,250 राशि प्रदान की जायेगी।
5. वृक्षारोपण हेतु समिति द्वारा निम्न सुझाव दिये जाते हैं:—
 - अ. कुल रोपित वृक्ष — 1600 न०.
 - ब. परियोजना प्रस्तावक संबंधित वन मंडलाधिकारी से सहमति प्राप्त करेंगे। सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं या स्थानीय ग्राम सभा/ वन विकास

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

समिति/पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य प्रथम वर्ष में संपादित किया जावेगा। यदि खनन अवधि में वृक्षारोपण संभव नहीं हो तो वृक्षारोपण हेतु समस्त राशि संबंधित ग्राम सभा/वन विकास समिति को जमा करके संबंधित जिला खनिज अधिकारी को सूचित करेगा।

6. वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के समस्त कार्यों के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर खनिज विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावे:-
7. पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	प्रथम वर्ष में नदी के किनारे 1 से 6 पंक्ति	1-3 पंक्ति - खास, नागरमोथा, लेमन ग्रास, अवेग के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानिए घास (150) 4-5 पंक्ति - कटंग बॉस, (100) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम, अर्जुन एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानिय प्रजातियाँ (100)	350
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	250
कुल			1600
टीप - उपरोक्तानुसार पौधारोपण का कार्य खनन क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय भूमि पर उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा एवं पंक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।			

8. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.27 लाख तथा प्रस्तावित सभी कार्य खनन अवधि समाप्ति के पूर्व में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम बिछोंदना स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य को राशि रु 27000/- प्रदाय कर संबंधित खनिज अधिकारी सूचित करेंगे। जिनके माध्यम से माध्यमिक विद्यालय के लिए टेबल-चेयर के सेट का वितरण किया जाएगा।	27,000

2. **Case No 9509/2022 M/s Pushpa Enterprises, Prop., Shri Anand Tamrakar, R/o H.No. B-23, Kasturba Nagar, Govindpura, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)- Prior Environment Clearance for Parai-1 Sand Quarry on Ken River in an area of 5.00 ha. (60000 Cum per annum) (Khasra No. 613/1), Village – Parai, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 613/1), Village – Parai, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 5.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 615वीं दिनांक 30/12/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार (ऑन लाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। यह रेत केन नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के कुछ भाग में पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वह रेत निकलने के कारण ऐसा दिख रहा है तथा खदान का वह भाग जिसमें पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र डूब में होने के कारण लगभग 2.31 हे० क्षेत्र डूबा हुआ है जो कि नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा लगभग 2.69 हे० क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। अतः वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार हो रही है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि ग्राम सभा की अनुमति अपलोड नहीं है, इस संबंध में संबंधित खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1011 दिनांक 12/5/23 के माध्यम से सूचित किया कि उनके द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को खदान की अनुमति देने के संबंध में पत्र लिखा गया था जो आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-73 के सरल क्रमांक-06 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-90,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा चाही गई वांछित मात्रा 60,000 घन मीटर प्रति वर्ष है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) से कम है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। यदि वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव किया जावेगा एवं तत्संबंध में राशि ग्राम पंचायत को दी जायेगी।

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. आवेदन पत्र अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 60,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.43 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय। विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 6.37 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयं वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव हेतु रु. 03.00 लाख एवं 10 परसेंट मैनेट्राइनेन्स के 30,000/वर्ष के साथ) पंचायत को राशि उपलब्ध करायेगे। पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे अथवा खनन अवधि जून, 2023 तक है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा यदि पौधारोपण कार्य में असहमति प्रकट की जाती है तो परियोजना प्रस्तावक अन्य सक्षम संस्था (जैसे स्थानीय पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था) को वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा सोपा जा सकता है तथा सी.ई.आर. की राशि यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन अवधि में पूर्ण की किये जाने की स्थिति में नहीं तो उक्त राशि को ग्राम पंचायत के खाते में जमा करा दी जाये तथा उक्त दोनों कार्य (वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर.) की क्रियान्वयन एवं मानिट्रिंग की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर खनिज विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावे :-
6. यदि ग्राम पंचायत द्वारा यदि पौधारोपण कार्य में असहमति प्रकट की जाती है तो परियोजना प्रस्तावक अन्य सक्षम संस्था (जैसे स्थानीय पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था) को वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा सोपा जा सकता है तथा सी.ई.आर. की राशि यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन अवधि में पूर्ण की किये जाने की स्थिति में नहीं तो उक्त राशि को ग्राम पंचायत के खाते में जमा करा दी जाये तथा उक्त दोनों कार्य (वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर.) की क्रियान्वयन एवं मानिट्रिंग की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर खनिज विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावे:-
7. वृक्षारोपण हेतु समिति द्वारा निम्न सुझाव दिये जाते हैं:-
 - अ. कुल रोपित वृक्ष – 6000 न0.
 - ब. परियोजना प्रस्तावक संबंधित वन मंडलाधिकारी से सहमति प्राप्त करेंगे। सहमति प्राप्त ना होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं या स्थानीय ग्राम सभा/ वन विकास

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

समिति/पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य प्रथम वर्ष में संपादित किया जावेगा। यदि खनन अवधि में वृक्षारोपण संभव नहीं हो तो वृक्षारोपण हेतु समस्त राशि संबंधित ग्राम सभा/वन विकास समिति को जमा करके संबंधित जिला खनिज अधिकारी को सूचित करेगा।

8. वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के समस्त कार्यों के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर खनिज विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावे:-
9. पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपसए गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (1,000) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (1,000) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1000)	3000
2.	परई के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2700
3.	परिवहन मार्ग में (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबी आँवला, कुसुम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	240
	शासकीय माध्यमिक शाला परई में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक , नीम, सीताफल, गुलमोहर , कुसुम इत्यादि।	60
कुल			6000
टीप - उपरोक्तानुसार पौधारोपण कार्य स्थानीय भूमि उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा एवं पंक्तियों की संख्या में किया जा सकता है।			

10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत परई को आर्थिक सहयोग किया जायेगा जिससे ग्राम पंचायत गांव में समर्सिबल लगाएगी तथा उसी के पास में पक्का चबूतरा बनाकर एक 1,000 लीटर टंकी रखी जाएगी	70,000
गाँव परई के ग्रामवासियों के लिए साल में दो बार रक्तचाप, मधुमेह और मौखिक स्वच्छता की जाँच के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगवाया जायेगा	10,000
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के विकास में तथा गांव के रोड निर्माण में आर्थिक सहयोग	20,000
	1,00,000

3. Case No 9716/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Lasangaon Sand Mine in an area of 14.00 ha. (2000 Cum per annum) (Khasra No. 2/1, 2/2/1/k, 46), Village-Lasangaon, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2/1, 2/2/1/k, 46), Village-Lasangaon, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 14.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 629वीं दिनांक 14/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वाटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह नर्मदा नदी के पास स्थित खोदू भरू प्रकृति की खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में झाड़ियों/ पेड़ के वजह होने के कारण लगभग 10.92 हे० क्षेत्र से नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा शेष भाग लगभग 3.08 हे० क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। अतः वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार हो रही है। क्योंकि उत्पादन मात्र 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-125 के सरल क्रमांक-5 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-2000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 2000 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके।

इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, सड़क/नाली की मरम्मत, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, गांव के लिये पीने का स्वच्छ पानी, ग्रामीणों का रोजगार एवं पॉलीथीन एवं अन्य खराब कचरों की निपटान इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—सी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 2000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 0.85 लाख ।
3. परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निम्न सुझाव दिये गये:—
अ. कुल 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण कर कार्य उपलब्ध भूमि पर खनन अवधि में करेंगे या निम्न स्थानों में परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण का कार्य संपादित करेंगे:—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :— स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेंगे।	आम, आवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1200
कुल			1200

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.32 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जायें :—

Corporate Environmental Responsibility		Capital
1	As per the Public hearing point – Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.	10000/-
2	Repairing of Village road and the drainage in village Lasangaon	10000/-
3	We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Lasangaon	12000/-
Total		32000/-

4. **Case No 7096/2020 Shri Vinod Kumar Godavarthi, Director, M/s National Energy Trading and Services Limited, R/o Plot No. 7, Bindu Sadan, 401, Sai Chandra Residency, Hyderabad, Rangareddi, TG-500089 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 24.970 ha. (1,63,350 cum per annum) (Khasra No. 1, 1, 288, 266), Village - Baspur/Shivsagar/Gonapur, Tehsil - Ghodadongari and Shahpur, Dist. Betul (MP).**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1, 1, 288, 266), Village - Baspur/Shivsagar/Gonapur, Tehsil - Ghodadongari and Shahpur, Dist. Betul (MP). 24.970 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 437वीं दिनांक 01/06/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

The EIA was presented by the PP and their consultant, during presentation as per Google image based on coordinates provided by PP, it was observed that the part of lease about 40% is submerged into the water from east side and a road bridge is located at a distance of 251 South-East side of the lease. आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद कुमार के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्विंटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह तवा नदी के पास स्थित खदान है परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में से नदी का प्रवाह होने के कारण लगभग 07.8 हे० क्षेत्र हुआ है जो कि नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा लगभग 15.98 हे० क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। अतः वांछित रेत की पूर्ति “रिप्लेनिशमेंट प्लान” के अनुसार हो रही है।

तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.49 के सरल क्रमांक 42 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल— 1,63,350 घनमीटर) उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1,63,350 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था, जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल के बराबर है।

स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है। समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सड़क को मरम्मत किया जाये, नदी किनारे कटाव को रोका जाये, वाहन की गति नियंत्रण रखी जावे, वृक्षारोपण, पीने के पानी की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य शिविर इत्यादि के सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी. अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 1,63,350 मी³ प्रति वर्ष।

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 01.68 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.99 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू-प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वयं वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
5. वृक्षारोपण हेतु समिति द्वारा निम्न सुझाव दिये जाते हैं:—
 - अ. कुल रोपित वृक्ष — 7110 न0.
 - ब. परियोजना प्रस्तावक संबंधित वन मंडलाधिकारी से सहमति प्राप्त करेंगे । सहमति प्राप्त ना होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं या स्थानीय ग्राम सभा/ वन विकास समिति/पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य प्रथम वर्ष में संपादित किया जावेगा। यदि खनन अवधि में वृक्षारोपण संभव नहीं हो तो वृक्षारोपण हेतु समस्त राशि संबंधित ग्राम सभा/वन विकास समिति को जमा करके संबंधित जिला खनिज अधिकारी को सूचित करेगा।
वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के समस्त कार्यों के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर खनिज विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावे:—
6. यदि ग्राम पंचायत द्वारा यदि पौधारोपण कार्य में असहमति प्रकट की जाती है तो परियोजना प्रस्तावक अन्य सक्षम संस्था (जैसे स्थानीय पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था) को वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा सोपा जा सकता है तथा सी.ई.आर. की राशि यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन अवधि में पूर्ण की किये जाने की स्थिति में नहीं तो उक्त राशि को ग्राम पंचायत के खाते में जमा करा दी जाये तथा उक्त दोनों कार्यों (वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर.) की क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर खनिज विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावे:—
7. पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:—

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Up to June 2023	For Village distribution specially to the famers who, land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	7000
Up to June 2023	Evacuation route with all protection as Tree Gaurd.	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi , Kadam and other local species.	110

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 07.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

Corporate Environmental Responsibility		
Proposal	Details	Budget in Lakh Rs
Maintenance of village road	Maintenance of village road (0.75km@2.00laks per km	1.50
Plant distribution	7000 trees will be distributed to villagers/local administrative office/NGOs	3.50
Erosion of river bank	One Layers of 1m width of sand bag with nagarmota ghas shall be developed at the bank of the river to prevent the erosion and 1500 no of kagang bans distribute to villagers of nearby river bank which is plant in 3row at river bank where is erosion observed	2.00
To provide drinking water facility	1 hand pump at village Shivsagar	0.50
Free health camp	One free health camp at village shivsagar	0.25
Total		7.25

5. Case No 9512/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, Bhopal (MP)-462013 Prior Environment Clearance for Alipura-2 Sand Quarry on Dhasan River in an area of 7.00 ha. (45000 Cum per annum) (Khasra No. 2113, New Khasra No. 1523), Village – Alipura, Tehsil - Naugaon, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2113, New Khasra No. 1523), Village – Alipura, Tehsil - Naugaon, Dist. Chhatarpur (MP) 7.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 615वीं दिनांक 30/12/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार यह रेत धसान नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के पूर्ण भाग में पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने

बताया कि खदान के जिस भाग में पानी भरा है वह रेत निकलने के कारण ऐसा दिख रहा है तथा खदान का वह भाग जिसमें पानी भरा है वहाँ पर खनन नहीं किया जायेगा खनन कार्य लगभग 4.20 हे. में किया जाना प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 965 दिनांक 09/5/23 खनिज अधिकारी को पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख है कि खदान क्षेत्र में अप्रैल माह से माह मई तक जल भराव कम हो जाता है जिससे खदान में उत्खनन कार्य किया जा सकता है । परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-77 के सरल क्रमांक-39 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-1,25,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरण स्वीकृति 45,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाही गया है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) के अनुरूप है ।

इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, रोजगार, मच्छरो से बचाव हेतु दवा का छिड़काव, नालियों की सफाई, गांव के लिये पीने का पानी की व्यवस्था इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। यदि वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव किया जावेगा एवं तत्संबंध में राशि ग्राम पंचायत को दी जायेगी । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी. अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 45,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.96 लाख प्रति वर्ष ।

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण प्रथम वर्ष (दिनांक 30.6.2023 तक) में किया जावेगा। अथवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण योजना में होने वाले व्यय को संबंधित ग्राम पंचायत अथवा वन विभाग को निर्धारित राशी 04.00 और 10 परसेंट रख रखाव के लिए 40,000/- राशि प्रदान की जायेगी । यदि ग्राम पंचायत द्वारा यदि पौधारोपण कार्य में असहमति प्रकट की जाती है तो परियोजना प्रस्तावक अन्य सक्षम संस्था (जैसे स्थानीय पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था) को वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा सोपा जा सकता है तथा सी.ई.आर. की राशि यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन अवधि में पूर्ण की किये जाने की स्थिति में नहीं तो उक्त राशि को ग्राम पंचायत के खाते में जमा करा दी जाये तथा उक्त दोनों कार्यों (वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर.) की क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर खनिज विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावे:-
5. वृक्षारोपण हेतु समिति द्वारा निम्न सुझाव दिये जाते हैं:-
 - अ. कुल रोपित वृक्ष - 8400 न0.
 - ब. परियोजना प्रस्तावक संबंधित वन मंडलाधिकारी से सहमति प्राप्त करेंगे । सहमति प्राप्त ना होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं या स्थानीय ग्राम सभा/ वन विकास समिति/पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य प्रथम वर्ष में संपादित किया जावेगा। यदि खनन अवधि में वृक्षारोपण संभव नहीं हो तो वृक्षारोपण हेतु समस्त राशि संबंधित ग्राम सभा/वन विकास समिति को जमा करके संबंधित जिला खनिज अधिकारी को सूचित करेगा।

वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के समस्त कार्यों के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर खनिज विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावे:-
6. पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (2,000) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (1,000) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (1000)	4,000
2	ग्राम- हरपालपुर, नायगाव, भांडरा, धकारवारा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4180

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2023

3	परिवहन मार्ग में (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल, जंगल जलेबीए, आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	160
	शासकीय कन्या हाई स्कूल अलीपुरा	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक, नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि।	60
कुल			8400

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा प्रस्तावित सभी कार्य खनन अवधि समाप्ति के पूर्व में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
गांव अलीपुरा की साफ-सफाई तथा दवा छिड़काव हेतु आर्थिक सहयोग	10,000
गांव अलीपुरा में हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना की जाएगी।	60,000
योग	70,000

6. Case No 9725/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Rajpura Sand Mine in an area of 11.00 ha. (1500 Cum per annum) (Khasra No. 38, 40, 41/1), Village-Rajpura, Tehsil-Manawar, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 38, 40, 41/1), Village-Rajpura, Tehsil-Manawar, District-Dhar (MP) 11.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 629वीं दिनांक 14/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वाटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह खोदू भरू खदान है जो मौसमी नदी के समीप स्थित है तथा यह नदी दक्षिण दिशा में नर्मदा में मिलती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खोदू भरू खदान के दक्षिण-पूर्व दिशा से एक नाला नदी में मिल रहा है एवं खदान के दक्षिणी सीमा नाले के समीप है तथा उक्त नाले पर एक पुल निर्मित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान पुल,

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

खदान के दक्षिण-पूर्व दिशा से एक नाला नदी में मिलने के कारण लगभग 04.66 हे०. क्षेत्र नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा शेष भाग लगभग 04.39 हे०. क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। अतः वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार हो रही है

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-126 के सरल क्रमांक-23 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-1500 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1500 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 1500 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। खदान की जन सुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, ग्रामीणों का रोजगार इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-सी. अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 1500 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 0.65 लाख ।
3. परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निम्न सुझाव दिये गये:-
 - अ. कुल 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण कर कार्य उपलब्ध भूमि पर खनन अवधि में करेंगे या निम्न स्थानों में परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण का कार्य संपादित करेंगे:-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :- स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेंगे।	आम, आवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1000
कुल			1000

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.28 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जायें :-

Corporate Environmental Responsibility		Capital
1	Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded	10000/-

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2023

	cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.	
2	Repairing of Village road and the drainage in village Rajpura	8000/-
3	Tenshed at shamshan ghat Rajpura	10000/-
Total		28000/-

7. Case No 9729/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Nanoda Sand Mine in an area of 8.00 ha. (2000 Cum per annum) (Khasra No. 1, 340), Village-Nanoda, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1, 340), Village-Nanoda, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) 8.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 629वीं दिनांक 14/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वांटि इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह रेत खदान भूरी नदी पर स्थित है जो दो भागों में आवंटित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र नदी के प्रवाह में होने के कारण लगभग 02.12 हे०. नॉन माइनिंग क्षेत्र प्रस्तावित है तथा लगभग 05.88 हे०. क्षेत्र खनन क्षमता 2000 घनमीटर के लिये उपयुक्त है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-127 के सरल क्रमांक-6 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-2000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 2000 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। खदान की जन सुनवाई

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिडकाव, ग्रामीणों का रोजगार इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी. /सीईआर में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी. अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 2000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 0.65 लाख।
3. परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निम्न सुझाव दिये गये:-
कुल 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण कर कार्य उपलब्ध भूमि पर खनन अवधि में करेंगे या निम्न स्थानों में परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण का कार्य संपादित करेंगे:-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :- स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेंगे।	आम, आवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1200
कुल			1200

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जायें :-

Corporate Environmental Responsibility	Capital
Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.	10000/-
Repairing of Village road and the drainage, in village Nanoda	10000/-
Teen shed at shamshan ghat in village Nanoda	10000/-
Total	30000/-

8. Case No 9726/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Morgadi Sand Mine in an area of 7.00 ha. (2000 Cum per annum) (Khasra No. 132/1), Village- Morgadi, Tehsil- Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 132/1), Village- Morgadi, Tehsil- Dharampuri, District-Dhar (MP) 7.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 629वीं दिनांक 14/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वाटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह नर्मदा नदी की खोदू भरू खदान है जो नर्मदा नदी से लगभग 70 मी. की दूरी पर स्थित है परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में झाड़ियों/ पेड़ के वजह होने के कारण लगभग 04.81 हे० क्षेत्र से नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा शेष भाग लगभग 02.19 हे० क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-125 के सरल क्रमांक-3 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-2000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, सड़क/नाली की मरम्मत, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, गांव के लिये पीने का स्वच्छ पानी, ग्रामीणों का रोजगार एवं पॉलीथीन एवं अन्य खराब कचरों की निपटान इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 2000 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक- सी. अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 2000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 0.90 लाख।
3. परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निम्न सुझाव दिये गये:-
कुल 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण कर कार्य उपलब्ध भूमि पर खनन अवधि में करेंगे या निम्न स्थानों में परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण का कार्य संपादित करेंगे:-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :- स्थानीय आंगनवाड़ी,	आम, आंवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू,	1500

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2023

स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेंगे।	इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियां	
कुल		1500

4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जायें :-

Corporate Environmental Responsibility		Capital
1	As per the Public Hearing pint :- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.	10000/-
2	Repairing of Village road and the drainage in village Morgadi	10000/-
3	We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Morgadi	12000/-
4	Teen Shed at Shamshan Ghat	8000/-
Total		40000/-

9. Case No 9717/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Kapsi Sand Mine in an area of 10.3660 ha. (1000 Cum per annum) (Khasra No. 1, 236, 582, 592, 685), Village-Kapsi, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1, 236, 582, 592, 685), Village-Kapsi, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) 10.3660 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 629वीं दिनांक 14/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वांटिफ इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह रेत उरी बागनी नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसंधान खदान क्षेत्र नदी के कन्फ्लूएंस के अपस्ट्रीम में स्थित है तथा पांच भागों में आवंटित है। लीज के पश्चिमी किनारे से नदी की धारा निकल रही है तथा एक स्टॉप डेम खदान क्षेत्र

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

से 752 मी. डाउन स्ट्रीम में स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान का वह भाग जो नदी से दूर है, उसके भी कुछ ही भाग में खनन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि उत्पादन मात्र 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में से नदी का प्रवाह होने के कारण लगभग 03.366 हे० क्षेत्र हुआ है जो कि नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा लगभग 07.00 हे० क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। अतः वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार हो रही है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-127 के सरल क्रमांक-30 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-1000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 1000 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। खदान की जन सुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, ग्रामीणों का रोजगार इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी. अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 1000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 0.85 लाख।
3. परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निम्न सुझाव दिये गये:-
कुल 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण कर कार्य उपलब्ध भूमि पर खनन अवधि में करेंगे या निम्न स्थानों में परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण का कार्य संपादित करेंगे:-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :- स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेंगे।	आम, आवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1200
कुल			1200

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.42 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

Corporate Environmental Responsibility		Capital
1	Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.	10000/-
2	Repairing of Village road and the drainage in village Kapsi	10000/-
3	We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Kapsi	12000/-
4	Cleaning of Uri Bagni River, providing nets to villagers, and awareness programme towards the river cleanliness, near Kapsi Village	10000/-
Total		42000/-

10. Case No 9736/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Imlipura Sand Mine in an area of 6.506 ha. (2300 Cum per annum) (Khasra No. 1, 59, 60, 77), Village- Imlipura, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1, 59, 60, 77), Village- Imlipura, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 6.506 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 628वीं दिनांक 13/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वांटि इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल यह रेत खदान कारम नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के कुछ भाग में नदी का पानी भरा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के जिस भाग से नदी का पानी है । इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में से नदी का प्रवाह होने के कारण लगभग 03.916 हे० क्षेत्र नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा लगभग 02.59 हे० क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है।

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-126 के सरल क्रमांक-18 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-2550 घनमीटर उल्लेखित है तथा पर्यावरण स्वीकृति 2300 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) से कम है। खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, सड़क/नाली की मरम्मत, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, गांव के लिये पीने का स्वच्छ पानी, ग्रामीणों का रोजगार एवं पॉलीथीन एवं अन्य खराब कचरों की निपटान इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 2300 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी. अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 2300 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 01.00 लाख।
3. परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निम्न सुझाव दिये गये:-
कुल 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण कर कार्य उपलब्ध भूमि पर खनन अवधि में करेंगे या निम्न स्थानों में परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण का कार्य संपादित करेंगे:-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :- स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेंगे।	आम, आवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1500
कुल			1500

4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.32 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जायें :-

Corporate Environmental Responsibility	Capital
As per Public Hearing Points :- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.	10000/-

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2023

Repairing of Village road and the drainage in village Implipura	10000/-
We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Implipura	12000/-
Total	32000/-

11. Case No 9735/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Bhavgaon Sand Mine in an area of 7.00 ha. (2000 Cum per annum) (Khasra No. 114/1), Village-Bhavgaon, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 114/1), Village-Bhavgaon, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 7.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 628वीं दिनांक 13/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वांटि इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल यह खोदू-भरू रेत खदान नर्मदा नदी के पास शासकीय भूमि पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में झाड़ियों/ पेड़ के वजह होने के कारण लगभग 06.00 हे० क्षेत्र से नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा शेष भाग लगभग 01.00 हे० क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-125 के सरल क्रमांक-02 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-2,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 2,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) के बराबर है।

परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 2000 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, सड़क/नाली की मरम्मत, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, गांव के लिये पीने का स्वच्छ पानी, ग्रामीणों का रोजगार एवं पॉलीथीन एवं अन्य खराब कचरों की निपटान इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक – सी. अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 2000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 0.90 लाख।
परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निम्न सुझाव दिये गये:—
कुल 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण कर कार्य उपलब्ध भूमि पर खनन अवधि में करेंगे या निम्न स्थानों में परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण का कार्य संपादित करेंगे:—

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :— स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेंगे।	आम, आवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1500
कुल			1500

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :—

Corporate Environmental Responsibility	Capital
As per Public Hearing Points :- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.	10000/-
Repairing of Village road and the drainage in Village Bhavgaon	10000/-
We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Bhavgaon	12000/-
Teen Shed at Shamshan Ghat in Village Bhavgaon	8000/-
Total	40000/-

12. Case No 9734/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Bhavariya Sand Mine in an area of 9.00 ha. (850 Cum per annum) (Khasra No. 284, 309, 322), Village-Bhavariya, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 284, 309, 322), Village-Bhavariya, Tehsil-Kukshi,

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

District-Dhar (MP) 9.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 628वीं दिनांक 13/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकाजुर्न राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वाटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल यह खोदू-भरू रेत खदान उरी बागनी नदी के पास शासकीय भूमि पर लगभग 150 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान दो भागों में आवंटित की गई है (एक भाग 6.0 हे. तथा दूसरा भाग 3.0 हे.)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में से नदी का प्रवाह होने के कारण लगभग 03.00 हे० क्षेत्र हुआ है जो कि नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा लगभग 06.00 हे० क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। अतः वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार हो रही है।

परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-127 के सरल क्रमांक-28 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-850 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर भी 850 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) के बराबर है।

परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 850 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। खदान की जन सुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, ग्रामीणों का रोजगार इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 850 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 0.55 लाख।
3. परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निम्न सुझाव दिये गये:-
कुल 800 वृक्षों का वृक्षारोपण कर कार्य उपलब्ध भूमि पर खनन अवधि में करेंगे या निम्न स्थानों में परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण का कार्य संपादित करेंगे:-

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2023

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :- स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेंगे।	आम, आवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियाँ	800
कुल			800

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

Corporate Environmental Responsibility	Capital
Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.	10000/-
Repairing of Village road and the drainage in Village Bhavariya	10000/-
Total	20000/-

13. Case No 9718/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Birlai Sand Mine in an area of 8.00 ha. (1200 Cum per annum) (Khasra No. 83, 319), Village- Birlai, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 83, 319), Village- Birlai, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) 8.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 629वीं दिनांक 14/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रिएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

गूगल इमेज अनुसार यह रेत उरी बागनी नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के दक्षिणी-पूर्वी भाग से नदी की धारा निकल रही है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि नदी का प्रवाह के कारण लगभग 03.5 हे० क्षेत्र हुआ है जो कि नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा लगभग 04.5 हे० क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। अतः वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार हो रही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-127 के सरल क्रमांक-26 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल-1200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1200 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 1200 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। खदान की जन सुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिडकाव, ग्रामीणों का रोजगार इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 1200 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 01.00 लाख।
3. परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निम्न सुझाव दिये गये:-
कुल 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण कर कार्य उपलब्ध भूमि पर खनन अवधि में करेंगे या निम्न स्थानों में परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण का कार्य संपादित करेंगे:-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :- स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेंगे।	आम, आवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1500
कुल			1500

4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.42 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जायें :-

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2023

Corporate Environmental Responsibility		Capital
1	Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.	10000/-
2	Repairing of Village road and the drainage in Village Birlai	10000/-
3	We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Birlai	12000/-
4	Cleaning of Uri Bagni Rived, providing nets to villagers, and awareness programme towards the river cleanliness near Birlai.	10000/-
Total		42000/-

14. Case No 9727/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Banki Sand Mine in an area of 5.782 ha. (1250 Cum per annum) (Khasra No. 251, 351), Village- Banki, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 251, 351), Village- Banki, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) 5.782 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 629वीं दिनांक 14/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रिएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह रेत भूरी नदी पर दो भागों में स्वीकृत है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-127 के सरल क्रमांक-29 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-1250 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1250 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में से नदी का प्रवाह होने के कारण लगभग 02.242 हे० क्षेत्र हुआ है जो कि नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा लगभग 03.54 हे० क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 1250 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। खदान की जन सुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिडकाव, ग्रामीणों का रोजगार इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 1250 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 0.75 लाख।
3. परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निम्न सुझाव दिये गये:-
कुल 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण कर कार्य उपलब्ध भूमि पर खनन अवधि में करेंगे या निम्न स्थानों में परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण का कार्य संपादित करेंगे:-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :- स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की माँग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेंगे।	आम, आवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1000
कुल			1000

4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.32 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जायें :-

Corporate Environmental Responsibility	Capital
Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.	10000/-
Repairing of Village road and the drainage in Village Banki	10000/-
We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Banki	12000/-
Total	32000/-

15. Case No 9723/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Pipalagadi Sand Mine in an area of 26.50 ha. (3650 Cum per annum) (Khasra No. 205/1, 21/2/1, 228/1/1, 229/1/1, 229/9/1/1, 229/9/4, 36/1), Village- Pipalagadi, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 205/1, 21/2/1, 228/1/1, 229/1/1, 229/9/1/1, 229/9/4, 36/1), Village- Pipalagadi, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 26.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 629वीं दिनांक 14/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स किएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह नर्मदा नदी की खोद भरू खदान है जो पांच भागों में आवंटित है और गूगल इमेज अनुसार अनुसंधान क्षेत्र में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि खदान क्षेत्र में झाड़ियों/पेड़ों के वजह होने के कारण लगभग 18.88 हे० क्षेत्र से नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा शेष भाग लगभग 07.62 हे० क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-125 के सरल क्रमांक-4 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-3650 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3650 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 3650 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, सड़क/नाली की मरम्मत, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, गांव के लिये पीने का स्वच्छ पानी, ग्रामीणों का रोजगार एवं पॉलीथीन एवं अन्य खराब कचरों की निपटान इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक- सी. अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 3650 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 01.45 लाख।
3. परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य:-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :- स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेंगे।	आम, आवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2200
कुल			2200

4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.32 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जायें :-

Corporate Environmental Responsibility		Capital
1	As per the Public Hearing Point :- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.	10000/-
2	Repairing of Village road and the drainage in village pipilasadi	10000/-
3	We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Piplagadi	12000/-
Total		32000/-

16. Case No 9728/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Shahpura Sand Mine in an area of 9.00 ha. (2000 Cum per annum) (Khasra No. 118/1, 118/2), Village-Shahpura, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 118/1, 118/2), Village-Shahpura, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 9.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 629वीं दिनांक 14/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वाटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार यह खोदू भरू खदान नर्मदा नदी के समीप स्थित है। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में झाड़ियों/पेड़ के वजह होने के कारण लगभग 06.5 हे०. क्षेत्र से नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा शेष भाग लगभग 02.5 हे०. क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-125 के सरल क्रमांक-6 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-2000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था, जो अधिक है।

परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 2000 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, सड़क/नाली की मरम्मत, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, गांव के लिये पीने का स्वच्छ पानी, ग्रामीणों का रोजगार एवं पॉलीथीन एवं अन्य खराब कचरों की निपटान इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक- सी. अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 2000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु.01.35 लाख।
3. परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निम्न सुझाव दिये गये:-
कुल 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण कर कार्य उपलब्ध भूमि पर खनन अवधि में करेंगे या निम्न स्थानों में परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण का कार्य संपादित करेंगे:-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :- स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों	आम, आवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2000

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2023

के मध्य कार्य किये जायेंगे।		
	कुल	2000

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.32 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :-

Corporate Environmental Responsibility	Capital
Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.	10000/-
Repairing of Village road and the drainage	10000/-
We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Shahapur	12000/-
Total	32000/-

17. Case No 9733/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Naagjhiri Sand Mine in an area of 10.00 ha. (2000 Cum per annum) (Khasra No. 45/1/1/k, 45/2/k), Village-Naagjhiri, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 45/1/1/k, 45/2/k), Village-Naagjhiri, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 10.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 628वीं दिनांक 13/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वांटिटी इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार यह खोदू-भरू रेत खदान नर्मदा नदी के पास शासकीय भूमि पर लगभग 50 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान दो भागों में आवंटित की गई है (एक भाग 6.0 हे. तथा दूसरा भाग 4.0 हे.) जिसमें पहला भाग नर्मदा नदी से लगभग 50 मीटर दूर तथा दूसरा भाग नर्मदा नदी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में झाड़ियाँ होने के कारण लगभग 04.5 हे० क्षेत्र से नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा शेष भाग लगभग 05.5 हे० क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-125 के सरल क्रमांक-07 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-2,000

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 2,000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) के बराबर है ।

परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 2000 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, सड़क/नाली की मरम्मत, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, गांव के लिये पीने का स्वच्छ पानी, ग्रामीणों का रोजगार एवं पॉलीथीन एवं अन्य खराब कचरों की निपटान इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक— सी. अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 2000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 01.85 लाख ।
3. परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निम्न सुझाव दिये गये:—
कुल 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण कर कार्य उपलब्ध भूमि पर खनन अवधि में करेंगे या निम्न स्थानों में परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण का कार्य संपादित करेंगे:—

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :— स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेंगे।	आम, आवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियाँ	3000
कुल			3000

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जायें :-

Corporate Environmental Responsibility	Capital
As per the Public Hearing Points :- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to panchayat. The collection charges will be bared by our company.	10000/-

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2023

Repairing of Village road and the drainage in village naagjhiri	10000/-
We will provide a Boring for drinking water at village naagjhiri	60000/-
Total	80000/-

18. Case No 9732/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Nimola Sand Mine in an area of 7.00 ha. (9000 Cum per annum) (Khasra No. 181/2), Village- Nimola, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP).

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 181/2), Village- Nimola, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 7.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 629वीं दिनांक 14/03/2023 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 30/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुन राव के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वाटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान खोदुभरू (नर्मदा नदी) है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। गूगल इमेज अनुसार यह खोदू भरू खदान नर्मदा नदी के समीप स्थित है अतः प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से दूरी 144 मीटर है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में झाड़ियों/ पेड़ के वजह होने के कारण लगभग 02.5 हे०. क्षेत्र से नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा शेष भाग लगभग 04.5 हे०. क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-125 के सरल क्रमांक-1 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-9,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 9,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 9000 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, सड़क/नाली की मरम्मत, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, गांव के लिये पीने का स्वच्छ पानी, ग्रामीणों का रोजगार एवं पॉलीथीन एवं अन्य खराब कचरों की निपटान इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक— सी. अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेट — 9000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 01.35 लाख।
3. परियोजना प्रस्तावक को वृक्षारोपण हेतु निम्न सुझाव दिये गये:—
कुल 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण कर कार्य उपलब्ध भूमि पर खनन अवधि में करेंगे या निम्न स्थानों में परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण का कार्य संपादित करेंगे:—

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	निम्नलिखित स्थानों पर पौधों का रोपण/वितरण का कार्य खनन अवधि में किया जाएगा :— स्थानीय आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्रामसभा भवन, सामुदायिक भवन एवं किसानों की मांग के अनुसार उनके लिए फलदार पौधों का वितरण किया जावेगा एवं वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ग्रामीणों के मध्य कार्य किये जायेंगे।	आम, आवला, सीताफल, अमरुद, अचार, निबू, इमली, करंज, जामुन, लसोड़ा, एवं अन्य फलदार पेड़ एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2000
कुल			2000

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.32 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जायें:—

Corporate Environmental Responsibility	Capital
As per the public hearing points :- Arrangement shall be made for collection of plastic and discarded cloths in villages and the collected plastic & discarded cloths shall be given for disposal to local panchayat. The collection charges will be bared by our company.	10000/-
Repairing of Village road and the drainage in village Nimola	10000/-
We will provide a drinking water tank of 2000 liters in the village Nimola	12000/-
Total	32000/-

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु पर चर्चा।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला - बैतूल (संशोधित रेत खनिज).

बैतूल जिले की संशोधित (रेत खनिज) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बैतूल, म.प्र. के पत्र क्रमांक 963 दिनांक 30/05/2023 के माध्यम से आज दिनांक 30/05/2023 को श्री नरेश भूमरकर, सहायक ड्राफ्ट्समेन द्वारा प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का परीक्षण करने पर पाया गया कि:-

- 19 खदान क्षेत्र के रकबे, मात्रा एवं अक्षांश, देशांस आदि में संशोधन किया गया है। 19 संशोधित रेत खदानों की सूची निम्नानुसार है:-
19 रेत खदानों (दौंडी, मालवर, गौनापुर, बांसपुर/शिवसागर, खपरिया, झोली-1, झोली-2, विष्णुपुर कचलोरा-2, कचलोरा-3, आमढाना रैयत-1, आमढाना रैयत-2, आमढाना रैयत-3, सातलदेही, बटकीढोह, बाकुड़, चिखली आमढाना, सोनतलाई/समरतढाना, पतौवापुरा)
- जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 2023/05/26 को डी.एस.आर का अनुमोदन किया गया जिसको जिला स्तर पोर्टल पर दिनांक 2023/05/29 से दिनांक 2023/06/18 तक 21) दिवस हेतु (दावे आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु अपलोड किया गया है।
- प्रभारी अधिकारी बैतूल-जिला (खनिज शाखा) द्वारा उल्लेख किया गया कि उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट डी.एस.आर. 21 (दिवस पूर्ण होने पर यदि कोई दावा आपत्ति/सुझाव प्राप्त होता है तो उन सुझावों का तदानुसार निराकरण किया जाकर पुनः डी.एस.आर. संशोधित कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावेगी।

समिति द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का परीक्षण करने के उपरांत निम्न बिन्दुओं पर जानकारी पुनः अद्यतन कर संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की हार्ड कॉपी में समिति की आगामी प्रस्तावित बैठकों समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

- पूर्व में प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा वर्तमान में प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में काफी अंतर परिलक्षित हो रहा है जैसे पूर्व में गहराई 01 मीटर दर्शाई गई थी जो कि अब 02 मीटर गहराई दर्शाई जा रही है। अतः सेण्ड रिप्लेनिशमेंट कर्व तैयार कर जमा करावें तथा कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बैतूल द्वारा पूर्व में दिये गये रकबा क्षेत्र, 19 खदान क्षेत्र जिनमें संशोधन किया गया है व उस परिपेक्ष्य में भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-बैतूल द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा किये गये अध्ययन की जानकारी सेण्ड रिप्लेनिशमेंट कर्व सहित व अभिलेखों सहित प्रस्तुत करें।



(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 30 मई 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 30 मई 2023

22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 30 मई 2023

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 30 मई 2023

23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 30 मई 2023

34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 30 मई 2023

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 30 मई 2023

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2023

26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.

648वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 30 मई 2023

- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिचिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण । जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

